सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-26 अंक-21 7 से 21 नवम्बर, 2011 मुख्य संपादक - कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती मूल्य : 2 रुपये

महान नवम्बर क्रान्ति जिन्दाबाद

''साम्राज्यवाद है पूंजीवाद के विकास का सर्वोच्च स्तर और बीसवीं सदी में ही उस स्तर पर पहुंच गया था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय राज्य – जिनके गठन के बिना सामन्तवाद को उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं था – वे आज और ज्यादा पूंजीवाद के लिए यथेष्ठ नहीं रहे हैं। पूंजीवाद ने केन्द्रीकरण को इस तरह निर्मित कर डाला है कि उद्योग की सभी शाखा-प्रशाखाओं को धनकुबेरों के सिंडिकेटों, ट्रस्टों और एसोसियेशनों ने कब्जा लिया है और पूंजी के सम्राटों ने या तो उपनिवेश कायम करके या अन्य देशों को आर्थिक शोषण के हजारों तरह के जालों में फंसाकर लगभग सारी दुनिया को अपने बीच बांट लिया है।... सामन्तवाद के खिलाफ संघर्षरत जो पूंजीवाद कौम का मुक्तिदाता था वही पूंजीवाद साम्राज्यवादी चरित्र हासिल करके अब कौम के सबसे बड़े उत्पीड़क में तब्दील हो गया है। पहले जो पूंजीवाद प्रगतिशील था आज वह प्रतिक्रियावादी हो चुका है। उस पूंजीवाद ने आज उत्पादिका शक्तियों को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया है कि उपनिवेश सृष्टि, एकाधिकारी व्यवस्था, नाना सुयोग-सुविधओं और कौम पर हर तरह के उत्पीड़नों के जरिये पूंजीवाद को कृत्रिम रूप से बचाये रखा गया तो मानव समाज को या तो सालों साल, यहां तक कि कई दशकों तक 'महाशक्तियों' के सशस्त्र संघर्ष की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, या फिर उसके विकल्प के तौर पर समाजवाद की ओर जाना होगा।''

– लेनिन

'वाल स्ट्रीट आन्दोलन' के समर्थन में कोलकाता में जुलूस

पूंजीवादी लूट और लगातार बढ़ रही गैर बराबरी के खिलाफ चल रहे अमेरिका के वाल स्ट्रीट आन्दोलन के समर्थन में एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के आह्वान पर कोलकाता में विक्षोभ जुलूस को सम्बोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव कॉमरेड सोमेन बोस। यह तस्वीर अमेरिका की 'वाल स्ट्रीट जर्नल' पत्रिका के 20 अक्तूबर के अंक में छपी थी। (India.wsj.com)

गद्दाफी की नृशंस हत्या पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने धिक्कार जताया

एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 22 अक्तूबर को जारी एक बयान में कहा :

पश्चिमी साम्राज्वाद के घोर विरोधी के रूप में परिचित लिबिया के राष्ट्राध्यक्ष मुयम्मर गद्दाफी की जिस तरह नाटो एवं पश्चिमी साम्राज्यवाद की शह पाये हुए तथाकथित 'नेशनल ट्रानजिसनल काउंसिल' के विद्रोहियों ने नृशंस हत्या की है, उस पर हम पूरजोर धिक्कार जताते हैं। इस तरह 'मानवीय हस्तक्षेप' के नाम पर साम्राज्यवादी दुष्टों ने एक बर्बर अमानवीय काम किया है। यह बात साफ जाहिर है कि एक के बाद एक साम्राज्यवाद-विरोधी शासनों को ढाहने और उन सब देशों की तेल सम्पदा को लूटने का घृणित कार्यक्रम लेकर साम्राज्यवादी चल रहे हैं, उसी की धारावाहिकता में लोकतंत्र कायम करने के बहाने खुल्लमखुल्ला फौजी दखलअंदाजी करके आजाद लिबिया की शासन व्यवस्था को तख्तापलट करवाकर एक कठपुतली सरकार बिठाना ही साम्राज्यवादियों की एकमात्र मंशा है। लिबिया की घटना से यह बात एक बार फिर साबित हो गई है कि हर देश की जनता के अपना भविष्य खुद तय करने के अनुल्लंघनीय अधिकार का बुर्जुआ लोकतत्र के ये स्वयंभू अभिभावक हमले और हस्तक्षेप करने के जरिये बेपरवाह उल्लंघन करते जा रहे हैं।

यह बात सच है कि दूसरे तमाम पूंजीवादी देशों की तरह ही लिबिया की जनता को भी जबरदस्त बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं भुगतनी पड़ रही हैं और उनकी लोकतांत्रिक आशा-आकांक्षाएं भी निर्ममता से दबाई जा रही हैं। इसके नतीजे के तौर पर जनता का रोष भी विछिन्न-विक्षिप्त रूप में प्रकट हुआ है। लेकिन देश में एक सही क्रांतिकारी पार्टी, यहां तक कि किसी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष संगठन तक की नामौजूदगी की वजह से यह विक्षोभ सही रास्ते पर प्रवाहित नहीं हो पाया। इसका फायदा पश्चिमी साम्राज्यवादी डकैतों ने उठाया जो जहां अपने-अपने देश में लोकतंत्र के मुखौटे की आड़ में जनता के हर तरह के लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय-नीतियों को पैरों तले रोंद रहे हैं, प्रतिवाद-प्रतिरोध की आवाज को दबा रहे हैं, लोकतांत्रिक आन्दोलनों का बड़ी तत्परता से दमन कर रहे हैं, वहीं विदेश में बन्दूक की नौक पर 'लोकतंत्र का निर्यात' करने के 'पवित्र' अभियान में कूद पड़े हैं। एक देश की शासन व्यवस्था या सामाजिक ढांचा कैसा होगा यह सब तय करने के नागरिकों के सार्वभौम अधिकार को ही इस तरह साम्राज्यवादी बेहिचक पददलित कर रहे हैं। आज साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष और विश्व शांति के दुर्ग के तौर पर अगर पहले की तरह शक्तिशाली समाजवादी खेमा होता, तो साम्राज्यवादी लूटेरों का इतना साहस नहीं होता कि वे इस तरह बेरोकटोक डाकेजनी जारी रख पायें।

हम दोबारा फिर यह कहना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों की साम्राज्यवाद-विरोधी ताकतों ने अगर समग्र विश्वव्यापी साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन तेज करने का उद्देश्य लेकर तहेदिल से जल्द से जल्द अपनी एकता व एकजुटता कायम नहीं की, तो पश्चिम एशिया व दुनिया के बाकी भागों में साम्राज्यवादियों की भयंकर साजिश को रोका नहीं जा सकेगा, जो मानवजाति के लिए बड़ा खतरनाक होगा।

महिलाओं पर बढ़ते अपराधों के खिलाफ

राष्ट्रीय महिला सम्मेलन

29–30 नवम्बर, 2011 रवीन्द्र कलाक्षेत्र, बैंगलोर

उद्घाटन समारोह

उद्घाटन : **जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया** (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)

अतिथिगण : **जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्णा** (पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट)

परिचय : **डॉ. एच.जी. जयालक्ष्मी** (महासचिव, एआईएमएसएस)

अध्यक्षता : **श्रीमती छाया मुखर्जी** (अध्यक्ष, एआईएमएसएस)

समापन समारोह

अतिथिगण : **जस्टिस मलय सेनगुप्ता** (पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट)

जस्टिस सुरेश हासबेट (पूर्व जज मुम्बई हाई कोर्ट)

अध्यक्षता : **श्रीमती कृष्णा सेन** (कोषाध्यक्ष, एआईएमएसएस)

सांस्कृतिक कार्यक्रम

उद्घाटन : **डॉ. मल्लिका साराभाई** (अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त नृत्यांगना)

अतिथिगण : **जस्टिस डी.वी. शैलेन्द्र कुमार** (कर्नाटक हाई कोर्ट के जज)

गिरीश कसरावली (अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्देशक)

श्रीमती सतरूपा सान्याल (प्रसिद्ध फिल्म निर्देशका)

अध्यक्षता : **डॉ. सुधा कामथ** (उपाध्यक्ष, एआईएमएसएस)

ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन

महान नवम्बर क्रान्ति की यादगार सीख और सार्थकता

(गतांक से आगे)

बोल्शेविक पार्टी का जन्म

ट्रॉटस्की ने लेनिन-विरोधी और बोल्शेविक-विरोधी तमाम गुटों और विभिन्न वैचारिक रुझान वालों को एकजुट कर 1912 में 'अगस्त ब्लॉक(गठजोड़)' बनाया। ट्रॉटस्की ने कहा कि मैं न तो बोल्शेविकों के साथ हूँ और न ही मेंशेविकों के साथ। मैं मध्यमार्गी हूँ। इस बात का एलान कर और दूसर बात यह कि ट्रॉटस्कीपंथियों को लेकर उन्होंने 1910 के जनवरी महीने में लेनिन की इच्छा के खिलाफ केन्द्रीय कमेटी का प्लेनम बुलाया। इस प्लेनम के फैसले के अनुसार बोल्शेविकों ने तो अपना मुखपत्र प्रोलीतारी(सर्वहारा) निकालना बंद कर दिया था, पर मेंशेविकों और ट्रॉटस्कीपंथियों ने अपने मुखपत्र का प्रकाशन नहीं रोका। पार्टी-विरोधी इन तमाम ताकतों के खिलाफ संघर्ष करने के क्रम में बोल्शेविकों ने तमाम बोल्शेविकों को एकजुट कर एक स्वतंत्र बोल्शेविक पार्टी के निर्माण की जरूरत महसूस की। इसी लक्ष्य के मद्देनजर 1912 के जनवरी महीने में प्राग शहर में पार्टी की छठी कांग्रेस आयोजित हुई। इस कांग्रेस के बारे में स्तालिन ने लिखा था, ''इस कांग्रेस में बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच एक विभाजन रेखा खिंच गयी और पूरे देश के बोल्शेविक संगठनों को इकट्ठा कर बोल्शेविक पार्टी का निर्माण हुआ।'' इस प्रकार तमाम मेंशेविक अवसरवादी, लिकुइडेटर्स, ऑटजोविस्ट आदि संगठनों से मुक्त होकर आरएसडीएलपी एक मोनोलिथिक(अखण्ड) ढाँचे की नयी पार्टी 'बोल्शेविक पार्टी' में तब्दील हुई। यह सही लेनिनीय मॉडल की पार्टी के तौर पर उभरी।

स्तालिपिन प्रतिक्रिया के दौर में पूरे देश में, खास तौर से मजदूर-किसानों के बीच निराशा के जो काले बादल छाये हुए थे, तमाम अवसरवादी, ढुलमुल और बेईमान ताकतों से मुक्त होकर बोल्शेविक पार्टी महान लेनिन के सफल नेतृत्व में उपरोक्त हताशा को हटाते हुए फिर से क्रांतिकारी आंदोलन की ओर अग्रसर होकर नयी उमंग के साथ प्रगति के रास्ते पर चल पड़ी थी। मजदूर वर्ग के दुश्मनों और उनके एजेंटों के खिलाफ संघर्ष चलाते हुए बोल्शेविक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की ताकत को और सुदृढ़ किया और मजदूर वर्ग के साथ सम्पर्क में काफी इजाफा किया। 1912 की 5 मई को पार्टी के नये मुखपत्र 'प्राव्दा' (सच्चाई) दैनिक का प्रकाशन हुआ। उसी साल जार सरकार ने चौथी स्टेट ड्यूमा का अधिवेशन बुलाया। बोल्शेविक पार्टी ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर ड्यूमा के चुनाव में हिस्सा लिया और अपने छह प्रतिनिधियों को भेज पाने में सफल हुई। ड्यूमा को क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन के एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल कर और मेहनतकश जनता के मुखपत्र के रूप में 'प्राव्दा' जैसे अपने एक बेहतरीन अखबार के प्रकाशन के जरिये बोल्शविक पार्टी नयी पीढ़ी को प्रशिक्षित करने में लगी हुई थी।

1914 में 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के सवाल पर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने जो अभूतपूर्व निर्णय लिया था, उस विषय पर कुछ चर्चा की जरूरत है।

विश्व युद्ध, बोल्शेविक पार्टी और क्रांतिकारी आंदोलन

लेनिन ने दिखाया कि 19वीं सदी के अंत में विश्व पूँजीवाद साम्राज्यवाद के स्तर में पहुँच गया, जिसकी प्रधान विशेषता थी वित्तीय पूँजी का निर्यात। इसके लिए साम्राज्यवादी देशों को नये बाजार, नये उपनिवेशों पर कब्जा करना, निर्यात के लिए नये-नये क्षेत्र और कच्चे माल की तलाश करना लाजमी हो गया। साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक और सैन्य ताकतों का संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने राजनैतिक प्रभाव के विस्तार और एकाधिकारी पूँजीपति समूहों के लिए अधिकतम मुनाफा कमाने के मकसद से विश्व बाजार को नये सिरे से बाँटना चाहा। नये सिरे से बँटे बाजार के कौन कितने हिस्से पर कब्जा कर पायेगा, इसे लेकर तीव्र प्रतियोगिता ने ही साम्राज्यवादी युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। नतीजतन, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। जार शासनाधीन रूस, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रेट ब्रिटेन–इन देशों ने मिलकर एक गुट बनाया। विपक्ष में था जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की और अन्य कुछ देशों का गुट।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट संगठन, दूसरे इन्टरनेशनल में शामिल पार्टियाँ अगर मजदूर वर्ग के हित से विश्वासघात नहीं करतीं, तो युद्ध इतनी खौफनाक शक्ल अख्तियार नहीं कर सकता था। वरन् इससे इस युद्ध में दुनिया की कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने-अपने देश में मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहूलियत भी हो सकती थी। 'दुनिया के तमाम मजदूर अपने-अपने देश के पूँजीपतियों का मुनाफा बढ़ाने के मकसद से एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाने का अपराधी महसूस करते हैं।' 1912 में बासेल, स्वीट्जरलैण्ड में आयोजित दूसरे इन्टरनेशनल की विश्व कांग्रेस की यह घोषणा थी। लेकिन लेनिन की बोल्शेविक पार्टी को छोड़कर दुनिया की किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घोषणा के मुताबिक चलने की हिम्मत नहीं की। युद्ध शुरू होने के बाद इन सारी पार्टियों ने उग्र राष्ट्रवाद का शिकार होकर अपनी-अपनी 'पितृभूमि' की हिफाजत करने की आवाज उठायी थी। सिर्फ लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ही 'बासेल कांग्रेस' की घोषणा के प्रति अडिग रही। रूस में मेंशेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी उग्र राष्ट्रवाद का नारा देकर रूसी साम्राज्यवाद के पक्ष में खड़े हो गये। वे रूस में पूँजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच वर्ग-समझौते का विचार फैलाते रहे और दूसरे देशों के खिलाफ युद्ध में रूस के समर्थन में प्रचार करते रहे। साम्राज्यवादी बुर्जुआ वर्ग उपनिवेशों से लूटकर लायी गयी धन-दौलत से यूरोप में मजदूरों के ऊँचे तबके को ज्यादा मजदूरी और दूसरी सहूलियतों के नाम पर दरअसल रिश्वत देता रहा और इस तरीके से मजदूरों के बीच अभिजात (एरिस्टोक्रेट) मजदूर नेता पैदा हुए। इन मजदूर नेताओं ने दूसरे इन्टरनेशनल में शामिल पार्टियों के अंदर काफी प्रभाव कायम किया। नतीजतन, लेनिन को आगे चलकर दूसरे इन्टरनेशनल संगठन को विघटित कर देना पड़ा।

लेनिन ने देश के अंदर जिस तरह से मेंशेविकों के अवसरवादी विचारों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा था, उसी तरह से उनको दुनिया के कम्युनिस्ट आंदोलन में व्याप्त तरह-तरह की भ्रान्तियों, गलतफहमियों के खिलाफ भी गैर समझौतावादी ढंग से लगातार संघर्ष करना पड़ा। 1916 में लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'साम्राज्यवाद पूँजीवाद की चरम अवस्था' की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने दिखाया कि पूँजीवाद विकास के अंतिम स्तर में आकर अपनी प्रगतिशील भूमिका को खोकर परजीवी चरित्र के मरणासन्न पूँजीवाद में तब्दील हो गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूँजीवाद का जमाना अपने आप ही खत्म हो जायेगा। मजदूर वर्ग को क्रांति के धक्के से इस मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना होगा। लेनिन ने कहा, ''साम्राज्यवाद है सर्वहारा वर्ग द्वारा की जाने वाली सामाजिक क्रांति की पूर्व वेला''। उन्होंने साफ तौर पर दिखाया कि साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के इस युग में किसी एक पूँजीवादी देश में समाजवाद कायम करना संभव है। लेनिन के इस मूल्यांकन से विभिन्न देशों के सर्वहारा वर्ग ने समझ लिया कि वह अपने-अपने देश में राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ क्रांति सफल कर सकता है। इस चेतना ने दुनिया के विभिन्न देशों के सर्वहारा वर्ग के अंदर प्रेरणा का संचार किया।

बोल्शेविकों ने युद्ध की बजाय शांति स्थापना की संभावना को सर्वहारा क्रांति की सफलता के साथ जोड़ लिया। उन लोगों ने कहा कि सिर्फ सर्वहारा क्रांति ही साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंककर साम्राज्यवादी युद्ध को खत्म कर सकती है और सही मायने में शांति कायम कर सकती है। युद्ध, शांति और क्रांति के बारे में यही था उनका सैद्धांतिक और युद्धनीतिगत रवैया और इसी के आधार पर बोल्शेविकों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलायी थी। साम्राज्यवाद-पूँजीवाद के आम संकट के नतीजतन जो पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसने पूँजीवादी संकट को हल करने की बजाय संकट को और भी बढ़ा दिया था और इस प्रकार रूस की शासन-व्यवस्था और कमजोर हो गयी थी। साम्राज्यवादी युद्ध में मौत के अलावा आम आदमी की रोजमर्रा की जिन्दगी में जिस तरह से घोर विपत्ति की स्थिति पैदा हुई थी, उसके मद्देनजर लेनिन ने जार शासन के खिलाफ रूस के मजदूरों को सचेत किया और युद्ध तथा सारी समस्याओं की जड़ साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शासन व्यवस्था के खिलाफ जबर्दस्त हमला बोलने के मकसद से जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष को और तेज करने का आह्वान किया।

रूसी बुर्जुआ वर्ग इस गलत सोच को आम जनता के दिलो-दिमाग में बिठाने की जीतोड़ कोशिश कर रहा था कि 'यह साम्राज्यवादी युद्ध दरअसल आम जनता का युद्ध है'। रूसी बुर्जुआ वर्ग के इस पाखंडपूर्ण देशप्रेम को गढ़ने में मेंशेविकों की सक्रिय भूमिका थी। दृढ़ता के साथ इसका विरोध करते हुए बोल्शेविक युद्ध और बुर्जुआ वर्ग की साजिशों के खिलाफ देश के मजदूर-किसानों को संगठित करने के काम में तन-मन से लगे हुए थे। नौसेना और फौज के अंदर भी बोल्शेविकों ने प्रचार-कार्य चलाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि 'पूँजीवाद -साम्राज्यवाद ही असली दुश्मन है।' अगर अमन-चैन बहाल करना है, तो इस साम्राज्यवादी युद्ध को गृह युद्ध में तब्दील करना होगा। फौज को बंदूकों की नोंक अपने-अपने देश के शासक बुर्जुआ वर्ग की ओर ही तान देनी होगी।

बोल्शेविकों के विचार रूसी जनता के अनुभव से भी मेल खा रहे थे। युद्ध की बदौलत रूस के जमींदार और पूँजीपतियों ने सम्पदा का अंबार खड़ा कर लिया था। फिर उसी युद्ध की बदौलत मजदूर-किसानों की जिन्दगी में दुःख-तकलीफों और बदहाली का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। युद्ध में लाखों लोग मारे गये थे। युद्ध से तबाह रूस में महामारी से भी अनगिनत लोगों की मौत हुई थी। रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाने के कगार पर थी। करीब डेढ़ करोड़ नौजवान फौज में शामिल होने के लिए मजबूर किये गये थे। नतीजतन, देश में मजदूरों का भयावह संकट पैदा हो गया था। एक के बाद एक कारखाना बंद होता जा रहा था। खेती में पैदावार भी काफी घट गयी थी। देश की आम जनता और युद्ध के मोर्चे पर सैनिक भुखमरी की स्थिति में थे। कपड़े-जूते के अभाव में वे काफी दर्दनाक स्थिति में दिन काट रहे थे। रूस की कुल सम्पदा का अधिकांश इस खतरनाक युद्ध का निवाला बन रहा था। इधर जार की सेना युद्ध में लगातार हार का सामना कर रही थी। हथियारों के घोर अभाव के चलते जार की सेना जर्मनी की ताकतवर तोपों का सामना नहीं कर पा रही थी। इसी बीच खबर फैल गई कि जार का युद्ध मंत्री सुखोम्लिनोव अपने देश से गद्दारी कर युद्ध में जर्मनी की मदद कर रहा है और उस साजिश में जार के कुछ अन्य मंत्री और सेनाध्यक्ष भी शामिल हैं। इसलिए जार की फौज पीछे हटती रही और जर्मनी ने प्रबल पराक्रम के साथ एक के बाद एक पोलैण्ड और बाल्टिक प्रदेश का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। इस सब कुछ के मिलेजुले असर ने जार की सेना के खिलाफ मजदूर-किसानों, फौजियों और बुद्धिजीवियों की नफरत और आक्रोश को, युद्ध और जारशाही के खिलाफ जनता के क्रांतिकारी आंदोलनों को पूरे देश में और युद्ध के मोर्चों पर तेजी से फैला दिया।

राजमहल पर कब्जा करने की साजिश

रूस के पूँजीपतियों में भी धीरे-धीरे असंतोष फैलता जा रहा था। बिशप रासपुतिन सहित जार सरकार के प्रभावशाली व्यक्ति जिस तरह से जर्मनी से शांति-वार्ता करने की कोशिश कर रहे थे, उससे पूँजीपतियों को इस बारे में कोई शक नहीं रह गया था कि जार की ओर से युद्ध छेड़ने की कोशिश किसी भी तरह से सफल नहीं होगी। उन्हें डर था कि शायद जार जर्मनी के साथ अलग से शांति-वार्ता करेंगे। ऐसी स्थिति में रूस के पूँजीपति वर्ग ने जार द्वितीय निकोलस के खिलाफ बगावत कर उसके भाई मिखाइल रोमानोव को तख्तनशीन करने की साजिश रची थी। रोमानोव पूंजीपतियों का पसंदीदा आदमी था। इस राजमहल में तख्तापलट करवाकर पूँजीपति एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। पहला यह कि सत्ता हथिया कर साम्राज्यवादी युद्ध को जारी रखना; दूसरा, रूसी जनता के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की जो जबर्दस्त लहर पैदा हो रही थी, राजमहल में तख्तापलट के जरिये जार को बदल कर जनता को गुमराह करते हुए उस लहर को शांत कर देना।

जार सरकार यदि जर्मनी के साथ अलग से शांति-समझौता कर लेती, तो अंग्रेज और फ्रांसिसी सरकारें इस युद्ध के दौरान अपने एक मित्र को खो देतीं। सिर्फ यही नहीं, रूस से चुनिंदा सैनिकों की आपूर्ति भी बंद हो जाती। इसलिए राजमहल में तख्तापलट करवाकर जार द्वितीय निकोलस को सत्ता से हटाने के लिए अंग्रेज और फ्रांसिसी सरकारों ने रूस के पूँजीपति वर्ग का पूरी तरह से साथ दिया था।

इधर युद्ध में जैसे-जैसे रूसी फौज की शिकस्त हो रही थी, वैसे-वैसे देश की आर्थिक बदहाली में भी भयंकर इजाफा हो रहा था। 1917 के जनवरी-फरवरी महीने में खाद्य, कच्चे माल, ईंधन की आपूर्ति में अस्त-व्यस्तता की स्थिति पैदा हो गयी थी। पेट्रोग्राद और मास्को में खाद्य की आपूर्ति करीब-करीब ठप हो गयी थी। कल-कारखाने एक-एक कर बंद होने लगे थे। नतीजतन, काफी लोग बेरोजगार हो गये थे। इसीलिए रूसी जनता का बड़ा तबका इस निर्णय पर पहुँचने लगा था कि इस असहनीय स्थिति से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है निरकुंश

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दिल्ली एआईडीवाईओ द्वारा सेमिनार सम्पन्न

'भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तथा युवा वर्ग की समस्याएं' विषय पर दिल्ली एआईडीवाईओ की ओर से 16 अक्टूबर 2011 को सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली के विभिन्न इलाकों से नौजवानों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सेमिनार में पिछले दिनों चले भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन में नौजवानों की भागीदारी तथा बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं के साथ ही नशाखोरी, अपसंकृति और अश्लील प्रसारण द्वारा युवाओं को पथभ्रष्ट करने की शासकवर्ग की कुनीतियों के बारे में नौजवानों ने खुलकर चर्चा की तथा उपरोक्त समस्याओं के खिलाफ दिल्ली के नौजवानों को संगठित कर आंदोलन गठित करने का आह्वान किया।

सेमिनार की शुरूआत में नौजवानों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। त्रीनगर क्षेत्र के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुरेश तूफान तथा एसयूसीआई (सी) के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड हरीश त्यागी ने नौजवानों को सम्बोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी का व्यक्तिगत कुकृत्य नहीं है बल्कि यह इस पूंजीवादी व्यवस्था की देन है जो कि इस व्यवस्था के साथ ही समाप्त होगा। लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए इस व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन समय की मांग है। नौजवानों को इस आंदोलन में भाग लेना होगा तथा बेरोजगारी, नशाखोरी, अपसंस्कृति तथा सरकार द्वारा टी.वी तथा अन्य प्रचार माध्यमों से फैलायी जा रही अश्लीलता के खिलाफ जोरदार युवा आंदोलन से ही इसे रोक सकता है।

सभा के अंत में संगठन के अध्यक्ष कॉमरेड राकेश कुमार ने सेमिनार में भाग लेने वाले सभी नौजवानों का आभार व्यक्त किया तथा सेमिनार का संचालन संगठन की दिल्ली सचिव कॉ. प्रकाश देवी ने किया।

जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा

भागलपुर (बिहार) : जनजीवन की ज्वलन्त समस्याओं को लेकर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), सुलतानगंज प्रखण्ड इकाई द्वारा 13 अक्तूबर को प्रखण्ड विकास अधिकारी के समक्ष जन प्रदर्शन किया। शाहबाद चौक से जुलूस निकलकर स्टेशन होते हुए बीडीओ कार्यालय के सामने पहुंचा और वहां सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी इकाई के इंचार्ज कॉ. रोशन कुमार रवि ने 14 सूत्री मांगों पर अपनी बात रखी। इसके बाद एक प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में बीडीओ ने अपने स्तर से प्रखण्ड की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।

इस मौके पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) के राज्य कमेटी सदस्य व मुंगेर जिला सचिव कॉ. दीपक कुमार, भागलपुर जिला के कॉ. रविकुमार सिंह, हरिहर, उपेन्द्र मांझी, नरेश दास, इन्द्रदेव, रेखादेवी, विकास चौरसिया, जितेन्द्र सिंह, रूपेश कुमार, सुनिता देवी, श्यामदेव सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

एआईएमएसएस का शिक्षण शिविर सम्पन्न

ग्वालियर : एआईएमएसएस मध्य प्रदेश कमेटी की ओर से 1 व 2 अक्तूबर को एक शिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन संगठन की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड छाया मुखर्जी ने किया। इसमें राज्य भर से आई सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। शिविर में एआईएमएसएस के आदर्श एवं उद्देश्य तथा मार्क्सवाद व मानव समाज के विकास पर चर्चा हुई।

शिविर के अन्त में एआईएमएसएस की राज्य स्तरीय सांगठनिक कमेटी का गठन किया गया। कॉमरेड रचना अग्रवाल को इसकी संयोजिका नियुक्त किया गया।

सीएम को ज्ञापन सौंपा

दुर्ग (छ.ग.) : स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गत दिनों बालोद शहर में लगाये नेत्र शिविर में आँखों के ऑपरेशन के बाद मरीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, स्वास्थ्य विभाग लापरवाह बना रहा और कोई कदम नहीं उठाया। तीन मरीज मर गये और 45 मरीजों की आँखों की रोशनी चली गई। इस पूरी घटना के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन व राज्य शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कॉ. विश्वजीत हारोडे के नेतृत्व में संगठन ने 19 अक्टूबर को मुख्यमन्त्री के नाम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौपा जिसमें मांग की गई कि मृतकों के परिजनों एवं जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है उन्हें प्रर्याप्त मुआवजा दिया जाए, इस घटना के सभी दोषियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाए और सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाया जाये। शासन के इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ व मांगों के समर्थन में 21 सितम्बर को एआईडीवाईओ और एआईडीएसओ की ओर से प्रदर्शन किया गया और पटेल चौक पर सरकार का पुतला दहन किया गया।

पानी के निजीकरण के खिलाफ जनसम्मेलन

गुलाबी बाग : दिल्ली सरकार द्वारा पानी के निजीकरण-व्यापारीकरण की घोषणा की जाने पर एसयूसीआई(सी), की स्थानीय इकाई की ओर से प्रतापनगर में एक जनसम्मेलन किया गया। मुख्य वक्ता पार्टी की राज्य सांगठनिक कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. प्राण शर्मा के अलावा महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से कॉ. रितु कौशिक, एआईडीएसओ के प्रशांत और सत्यवती कॉलेज के अध्यापक प्रवीण व जसवीर कौर ने वक्तव्य रखे। एक 17 सदस्यीय जन कमेटी गठित की गई जिसमें जसवीर कौर को अध्यक्ष, रितु कौशिक, आशा, वीएल कपूर व मेहर सिंह को उपाध्यक्ष, प्रशांत को सचिव, संगीता को सहसचिव व अमरजीत को कोषाध्यक्ष चुना गया।

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 2 का शेष)

जारशाही का खात्मा करना। इसलिए यह बात साफ हो गयी थी कि जारशाही के खात्मे के दिन नजदीक आ गये हैं। रूसी पूँजीपति वर्ग इस संकटपूर्ण स्थिति का हल राजमहल में तख्तापलट करवाकर करना चाहता था, जबकि रूसी जनता का रास्ता इससे अलग था।

फरवरी क्रांति और जारशाही का पतन

1917 की 9 जनवरी को ही हड़ताल शुरू हो गयी। जुलूस, प्रदर्शन आदि के जरिये पेट्रोग्राद, मास्को, बाकू और निज्नी नवगोरड थर्रा उठा था। पुलिस जुल्म के बावजूद पूरे देश में आम हड़ताल को सफल बनाने की योजना के मुताबिक अधिक से अधिक संख्या में मजदूर इस आंदोलन में शामिल होने लगे थे।

उदारवादी बुर्जुआ जैसा चाहते थे, क्रांति के इस शुरूआती आंदोलन को मेंशेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। 14 फरवरी को ड्यूमा का सत्र शुरू होने वाला था। इस दिन मेंशेविकों ने ड्यूमा के समक्ष मजदूरों का जुलूस निकालने की योजना बनायी, लेकिन बोल्शेविकों के दिशा-निर्देश पर मजदूरों ने ड्यूमा के समक्ष न जाकर एक विरोध मार्च निकाला।

18 फरवरी, 1917 को पेट्रोग्राद के पुतिलोव कारखाने में हड़ताल शुरू हुई। 22 फरवरी तक ज्यादातर बड़े कारखानों को हड़ताल ने ठप कर दिया। 23 फरवरी (नये कैलेण्डर के अनुसार 8 मार्च) को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पेट्रोग्राद बोल्शेविक कमेटी के आह्वान पर महिला मजदूर भुखमरी, युद्ध और जारशाही के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आयीं। महिलाओं के इस आंदोलन को पेट्रोग्राद के मजदूरों ने समर्थन दिया। अगले दिन 24 फरवरी को हड़ताल की व्यापकता में काफी इजाफा हुआ और करीब 2 लाख मजदूरों ने इसमें शिरकत की।

25 फरवरी को पेट्रोग्राद के तमाम मजदूर हड़ताल में शामिल हो गए। हड़ताल से पूरा शहर ठप हो गया। हर जगह पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें होती रही। रास्तों पर एकताबद्ध मजदूरों के हाथों में लाल झंडा लहरा रहा था। उस पर 'जारशाही हो बर्बाद', 'युद्ध पर रोक लगाओ', 'हमें रोटी चाहिए' आदि नारे लिखे थे।

26 फरवरी को सुबह से ही प्रदर्शनों और हड़तालों ने जन उभार का रूप ले लिया। पुलिस और सेना से मजदूर हथियार छीनते रहे। जनमेनस्काया चौक पर पुलिस ने मजदूरों के जुलूस पर गोलियाँ चलायी। जार के सेनापति ने इस बगावत को दबाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसी दिन जार सरकार की पावलोवस्की रेजिमेंट की रिजर्व बटालियन की चौथी कंपनी ने पलटवार कर जार की घुड़सवार सेना पर ही गोलियाँ चला दी। सेना और पुलिस को प्रदर्शनकारियों के पक्ष में लाने की व्यापक कोशिश शुरू हो गयी। महिला मजदूरों की भी इस आंदोलन में काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। वे सीधे पुलिस और सेना के पास चली गयीं और जारशाही के बेरहम शासन के दौरान आम जनता की दुःख-दुर्दशा उनसे बयां की और इस प्रकार उन्होंने इस घृणित निरकुंश जार शासन को उखाड़ फेंकने में उनसे मदद देने की अपील की। उसी दिन बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने एक घोषणापत्र जारी कर जारशाही के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया और साथ ही एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की स्थापना का भी एलान कर दिया।

अगले दिन 27 फरवरी को पेट्रोग्राद में सेना ने मजदूरों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। असंतुष्ट सैनिकों की संख्या सैलाब की तरह बढ़ती गयी और वे झुंड के झुंड क्रांतिकारियों में शामिल होते रहे। 27 फरवरी की सुबह क्रांतिकारियों के साथ 10 हजार सैनिक आ मिले। शाम होते-होते यह संख्या 60 हजार पार कर गयी।

क्रांतिकारी मजदूर और सेना जार सरकार के मंत्रियों और सेनापतियों को गिरफ्तार करती रही। जेल में कैद क्रांतिकारियों को आजाद कर दिया गया। आजाद राजनैतिक कैदी तत्काल क्रांतिकारी लड़ाई में शामिल हो गये थे। सड़कों पर गोलीबारी और कुछ समय तक चलती रही, लेकिन जल्दी ही जार की सेना मजदूरों की तरफ आ मिली। नतीजतन, जारशाही का पतन अनिवार्य हो गया।

पेट्रोग्राद में क्रांतिकारियों की जीत की खबर जैसे ही रूस के अन्य शहरों तथा लड़ाई के मोर्चों पर फैली, मजदूर और सेना ने हर जगह जार सरकार के पदाधिकारियों को सत्ता से बेदखल करना शुरू कर दिया। रूस में फरवरी की बुर्जुआ जनवादी क्रांति सफल हुई, जारशाही का खात्मा हुआ।

फरवरी की बुर्जुआ जनवादी क्रांति इसलिए सफल हुई थी कि मजदूर वर्ग इस लड़ाई का अगुआ दस्ता था। वे ही सेना की वर्दी में 'अमन, रोटी और आजादी' की मांग लेकर आंदोलन में शामिल लाखों किसानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। क्रांति के शुरूआती दिनों में लेनिन ने लिखा है, ''इस क्रांति का रचयिता था सर्वहारा वर्ग। वे बहादुरी के साथ लड़े, अपना खून बहाये और गरीब मेहनतकश जनता के बड़े तबके को आन्दोलन की धारा में खींच लाये।'' (कलेक्टेड वर्क्स, वॉल्यूम-20)

मजदूर और सेना के प्रतिनिधियों की सोवियत

इस प्रसंग में सोवियतों की बात काफी उल्लेखनीय है। जारशाही के खिलाफ संघर्ष की आग उगलने वाले दिनों में रूस की मेहनतकश जनता ने खुद की पहल पर आंदोलन के नये और मजबूत हथियार 'मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियतों' का गठन किया था। कल-कारखानों के मजदूर प्रतिनिधियों को लेकर गठित ये सोवियतें मजदूरों के ऐसे जन संगठन थे, जो दुनिया की जनता ने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। 1905 में रूस में निर्मित ये सोवियतें सृजनात्मक जनता की क्रांतिकारी पहल के मूर्त रूप थीं। जारशाही के तमाम कायदे-कानूनों, सरकारी मनाही व प्रतिबंधों को तोड़कर जनता के क्रांतिकारी तबके को लेकर ही इन सोवियतों का निर्माण हुआ था। दरअसल इन सोवियतों ने ही वैकल्पिक राजसत्ता का रूप धारण कर लिया था।

क्रांति शुरू होने के पहले दिन से ही इन सोवियतों ने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। 1905 की क्रांति के दौरान सोवियतें एक तरफ हथियारबंद बगावत के संगठन के तौर पर, तो दूसरी तरफ एक नयी क्रांतिकारी ताकत के भ्रूण की शक्ल में काम कर रही थीं। सोवियतों के गठन के जरिये संघर्ष के संचालन की योजना को रूसी जनता ने पूरी तरह से अपना लिया था और जारशाही के खात्मे के तुरंत बाद ही वे असंख्य सोवियतों के निर्माण के काम में लग गये थे। 1905 में और 1917 में निर्मित सोवियतों के बीच एक फर्क था। 1905 में सोवियतों का निमार्ण सिर्फ मजदूरों के प्रतिनिधियों को लेकर ही हुआ था। लेकिन, 1917 में मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ

(शेष पृष्ठ 4 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 3 का शेष)

सेना के प्रतिनिधि भी शामिल थे। 1917 की फरवरी क्रांति में जो मजदूर और सेना के लोग शामिल हुए थे, उन्होंने 'मजदूर और सेना के प्रतिनिधियों की सोवियतों' का गठन किया था और क्रांति की सफलता के पीछे इन सोवियतों की भूमिका ही मुख्य थी।

अस्थायी सरकार की स्थापना

1917 की फरवरी क्रांति के दौरान बोल्शेविक जब सड़कों पर उतर कर जनता के संघर्ष में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, तब समझौतापरस्त मेंशेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी इन सोवियतों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा कर वहाँ बहुमत हासिल करने में मशगूल थे। बोल्शेविक पार्टी के ज्यादातर नेता उस दौरान या तो जेल में थे या निर्वासन में। इसलिए इस काम में उन्हें काफी दिक्कतें आयी थीं। नतीजतन, पेट्रोग्राद, मास्को सहित कुछ बड़े शहरों की सोवियतों का नेतृत्व मेंशेविकों और अन्य समझौतापरस्त पार्टियों के कब्जे में चला गया था। सिर्फ कुछ जगहों पर ही बोल्शेविक सोवियतों पर अपना कब्जा बरकरार रख पाये थे।

क्रांतिकारी मजदूरों और सैनिकों का मानना था कि सोवियतें क्रांतिकारियों की मांगें पूरी करेंगी और सबसे पहले वे शांति कायम करने का प्रयास जरूर करेंगी। लेकिन मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों की युद्ध खत्म कर शांति कायम करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। वे क्रांति की डावांडोल स्थिति का फायदा उठाकर रूसी बुर्जुआ वर्ग को सत्तासीन करना चाहते थे। इसी के मुताबिक 1917 की 27 फरवरी (नये कैलेंडर के अनुसार 12 मार्च) को चौथी ड्यूमा के उदारवादी सदस्यों ने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों और मेंशेविकों के साथ गोपनीय समझौते के जरिये स्टेट ड्यूमा की एक अस्थायी कमेटी का गठन किया। इसके कुछ दिनों बाद इस कमेटी ने सोवियत की कार्यकारिणी समिति के सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी और मेंशेविक नेताओं के साथ मिलकर रूस में एक अस्थायी सरकार के गठन के लिए समझौता किया। ये तमाम योजनाएँ बोल्शेविकों से छिपाकर बनायी गयी थीं। इस नयी अस्थायी सरकार में जो लोग शामिल हुए थे, उनमें रूस के पूँजीपति वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि और 'जनतंत्र' के प्रतिनिधि के रूप में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के केरेन्स्की शामिल हुए थे।

इस अस्थायी सरकार के गठन के जरिये सोवियत की कार्यकारिणी समिति के समझौतापरस्त नेताओं ने बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता सौंप दी। इस तरह से रूस में नयी राजसत्ता का जन्म हुआ। इसमें वे लोग थे, जिन्हें लेनिन के शब्दों में 'पूँजीपति तथा पूँजीपति वर्ग में तब्दील हो चुके जमींदार' कहा जाता है।

अस्थायी सरकार और दोहरी सत्ता की मौजूदगी

1917 की फरवरी क्रांति के बाद नवगठित अस्थायी बुर्जुआ सरकार के साथ-साथ रूस में एक और ताकत भी अपनी विशेषताओं को लेकर विराजमान थी। यह ताकत थी सोवियतें – मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित आम जनता की कमेटियाँ। सोवियतों के सैन्य प्रतिनिधियों में ज्यादातर किसान थे। युद्ध के दौरान जार के आदेश पर वे हथियार उठाने को मजबूर हुए थे। रूस की सोवियतें मजदूरों, किसानों और किसानों में से फौज में भर्ती हुए लोगों को लेकर जारशाही के खिलाफ निर्मित सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के संगठन थीं।

नतीजतन, तत्कालीन रूस में परस्पर विरोधी दो ताकतों, दोहरे अधिनायकत्व की मौजूदगी देखी गयी। एक तरफ थी अस्थाई सरकार, जिसके जरिये बुर्जुआ वर्ग का अधिनायकत्व प्रकट हो रहा था। दूसरी तरफ सर्वहारा वर्ग और किसानों का अधिनायकत्व था, जो मजदूर-किसानों के प्रतिनिधियों की सोवियतों के जरिये प्रकट हुआ था।

इस दोहरी सत्ता की व्याख्या करते हुए लेनिन ने कहा था, ''अस्थाई सरकार के साथ-साथ मजदूरों और सैनिकों की सोवियतें भी एक किस्म की सरकार है, जिसने कमजोर और प्राथमिक स्तर की होने के बावजूद निश्चित रूप से अपना अस्तित्व कायम कर रखा है।'' (लेनिन, कलेक्टेड वर्क्स, वॉल्यूम-14) पहले ही कहा जा चुका है कि 1917 की फरवरी क्रांति से पहले बोल्शेविक जब सड़कों पर उतरकर जनता के संघर्ष में नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उस दौरान सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी और मेंशेविक पार्टी सरीखी समझौतापरस्त पार्टियों ने पेट्रोग्राद, मास्को सहित काफी शहरों की सोवियतों की सीटों पर कब्जा जमा लिया था। इसलिए पूँजीपतियों के साथ गुप्त समझौता कर जब मेंशेविकों और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरियों ने अस्थायी सरकार का गठन किया और रूस के पूँजीपति वर्ग को राजसत्ता सौंप दी थी, तब बोल्शेविकों के विरोध के बावजूद ज्यादातर सोवियतों ने उनका समर्थन किया था। इसको व्याख्या करते हुए लेनिन ने दिखाया कि तत्कालीन रूस में मजदूर-किसान और छोटी-छोटी सम्पतियों के जो मालिक थे, उनमें ज्यादातर लोग राजनीति के बारे में अनुभवहीन थे और पेटी बुर्जुआ(निम्न पूंजीवादी) मानसिकता से प्रभावित थे। उन्होंने दिखाया कि इसी वजह से क्रांति की सफलता के मधुर स्वाद से मतवाले बहुसंख्यक अवाम समझौतापरस्त पार्टियों के प्रभाव में थे। उन्होंने बुर्जुआ वर्ग को राजसत्ता सौंप देने का समर्थन किया था। सरल विश्वास से उन लोगों ने सोचा था कि बुर्जुआ ताकतें सोवियतों के काम में रुकावट नहीं डालेंगी।

ऐसी परिस्थिति में अस्थायी सरकार का साम्राज्यवादी चरित्र और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों तथा मेंशेविकों का विश्वासघाती चरित्र बेनकाब कर जनता के सामने पेश करना बोल्शेविकों का फर्ज बन गया था। इसके साथ ही काफी धैर्य के साथ उन लोगों ने जनता को यह भी समझाने की कोशिश की थी कि अस्थायी सरकार को सत्ता से बेदखल कर सोवियतों को लेकर गठित सरकार के हाथों में जब तक राजसत्ता की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जायेगी, तब तक देश में अमन-चैन कायम नहीं हो पायेगा।

बोल्शेविक पार्टी ने इस दौरान आम जनता को इस बात को समझाने के तकलीफदेह काम में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। फरवरी क्रांति के 5 दिन बाद बोल्शेविक पार्टी का मुखपत्र 'प्राव्दा' फिर से प्रकाशित हुआ। धीरे-धीरे उदारवादी पूंजीपतियों, मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों से रूसी जनता का मोहभंग होने लगा और बोल्शेविक पार्टी ने जनता के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। पार्टी के कार्यकर्ता सैनिकों और किसानों को मजदूरों के साथ एकताबद्ध होकर काम करने की जरूरत समझाते रहे। वे किसानों को बताते रहे कि अगर क्रांति को आगे नहीं बढ़ाया गया और अस्थायी पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंककर सोवियत सरकार की स्थापना नहीं की गयी, तो जनता को रोटी, जमीन और अमन-चैन कुछ भी नहीं मिल पायेगा।

अस्थायी सरकार के काम-काज से बोल्शेविकों की बातों की सच्चाई जनता के सामने उजागर होती रही। धीरे-धीरे यही दिखायी दे रहा था कि अस्थायी सरकार न तो जनहित में और न ही अमन-चैन कायम करने के लिए काम कर रही है, बल्कि वह जनहित के खिलाफ है, युद्ध के पक्ष में है। यह सरकार जनता के लिए रोटी, जमीन और अमन-चैन कायम करने का इंतजाम कभी नहीं करेगी। मजदूर और सैनिक जब क्रांति के जरिये जारशाही को उखाड़ फेंकने के काम में आगे बढ़ रहे थे, तब अस्थायी सरकार निश्चित रूप से जारशाही को बचाने की कोशिश में जुटी थी। रूस के पूँजीपतियों और जमींदारों के प्रतिनिधियों को लेकर बनी अस्थायी सरकार की किसानों को उनकी जमीन वापस करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। इसी तरह आम आदमी को रोटी मुहैया कराने की बात भी उन्होंने कभी नहीं सोची थी। क्योंकि, ऐसा करने से उन्हें बड़े-बड़े अनाज व्यापारियों, जमींदारों, कुलकों और बड़े किसानों के खिलाफ काम करना पड़ता। चूँकि यह सरकार वास्तव में रूस के अमीर वर्ग के ही हितों की हिफाजत करने वाली थी, इसलिए इस काम को अंजाम देना उनके लिए नामुमकिन था। फिर, अंग्रेज और फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों के साथ गठजोड़ रहने की वजह से युद्ध खत्म करने का कोई इरादा इस अस्थायी सरकार का नहीं था। वरन् युद्ध के जरिये वे रूस के साम्राज्यवादी इरादों को ही अमली जामा पहनाना चाहते थे। धीरे-धीरे यही बात साफ होती जा रही थी कि 'दोहरी सत्ता' का मुद्दा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। राजसत्ता या तो अस्थायी सरकार, या फिर सोवियत सरकार–इन दोनों में से किसी एक को सौंपनी होगी।

फरवरी क्रांति के बाद की रूस की परिस्थितियाँ

बावजूद इसके मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों की तरह समझौतापरस्त पार्टियों के प्रति आम जनता के एक बड़े तबके का समर्थन था। उस समय भी उनका विश्वास था कि चुनी हुई सरकार बहुत जल्दी ही शांतिपूर्ण तरीके से सारी समस्याओं को सुलझा देगी। इधर, इस दौरान स्थायी सरकार ने क्रांतिकारी आंदोलनों पर गुपचुप तरीके से विभिन्न किस्म के हमले करने शुरू कर दिये थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अनुशासन बनाये रखने के नाम पर सरकार कभी-कभी जनता की स्वतंत्र जनवादी गतिविधियों के खिलाफ भी हमला बोल देती थी। लेकिन रूस के मजदूर और सैनिक हाल ही में हासिल किये गये अपने जनवादी अधिकारों, मसलन अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, धरना-जुलूस-प्रदर्शन आदि करने की आजादी का पूरी तरह से इस्तेमाल करते रहे ताकि वे देश की राजनीति में सक्रिय रूप से शिरकत करते हुए अक्लमंदी के साथ परिस्थिति का ठोस मूल्यांकन कर आगे का कार्यक्रम निर्धारित कर सकें।

जार के जमाने में बोल्शेविक पार्टी काफी जोखिम भरी स्थिति में अत्यंत गुप्त रूप से काम करने के लिए मजबूर थी। फरवरी क्रांति के बाद उन्होंने खुलेआम संगठन बनाना और राजनैतिक गतिविधियाँ करना शुरू कर दिया। बोल्शेविक पार्टी के विभिन्न संगठनों में सदस्यों की संख्या 40-45 हजार से अधिक नहीं थी। लेकिन, संख्या में कम होने के बावजूद संघर्ष की आग में तपे-तपाये ये लोग क्रांति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे।

लेनिन की स्वदेश वापसी और अप्रैल थीसिस

इसी दौरान बोल्शेविक पार्टी के अंदर सैद्धांतिक विरोध शुरू हो गया। कामेनेव, राइकोव, बुबनोव आदि नेता अस्थाई सरकार को सशर्त समर्थन देने की बात कर रहे थे। स्तालिन, मोलोतोव और ज्यादातर नेताओं ने इसका विरोध किया। स्तालिन तभी निर्वासन से लौटे थे। उन्होंने साम्राज्यवादी युद्ध के खिलाफ संघर्ष का एलान किया। ऐसे वक्त में लेनिन की नेतृत्वकारी भूमिका का अभाव खल रहा था।

अंततः 3 अप्रैल, 1917 (नये कैलेंडर के अनुसार 16 अप्रैल) को लम्बे निर्वासन के बाद लेनिन रूस पहुँचे। फिनलैण्ड के रेलवे स्टेशन परिसर में जुटे हजारों मजदूरों और सैनिकों के समक्ष एक बख्तरबंद गाड़ी पर खड़े होकर लेनिन ने अपने भाषण में समाजवादी क्रांति को सफल बनाने के संघर्ष में आगे आने का आह्वान किया।

रूस लौटकर लेनिन क्रांति को संगठित करने के काम में पूरी तरह से कूद पड़े। अपने देश लौटने के अगले ही दिन बोल्शेविकों की एक सभा में उन्होंने युद्ध और क्रांति पर एक रिपोर्ट पेश की। बाद में यही रिपोर्ट उन्होंने एक अन्य सभा में भी पेश की। उस सभा में बोल्शेविकों के साथ मेंशेविक भी मौजूद थे। यही रिपोर्ट लेनिन की मशहूर 'अप्रैल थीसिस' का आधार थी। अप्रैल थीसिस ने बोल्शेविक पार्टी और सर्वहारा वर्ग के सामने बुर्जुआ जनवादी क्रांति से समाजवादी क्रांति में जाने की क्रांतिकारी लाइन और संघर्ष की योजना को साफ तौर पर पेश कर दिया। क्रांति की योजना और उसे सफल बनाने में बोल्शेविक पार्टी के कार्यभार में अप्रैल थीसिस का असाधारण महत्व था। इस थीसिस में समाजवादी क्रांति में जाने के बुनियादी चरणों के बारे में सैद्धांतिक योजनाओं की साफ तौर पर चर्चा की गयी थी।

आर्थिक क्षेत्र में ये योजनाएँ निम्न थीं: सारी जमीनों का राष्ट्रीयकरण और जमींदारी जब्त करना; सारे बैंकों को मिलाकर एक ही राष्ट्रीय बैंक के तहत लाना, जिसका संचालन मजदूर प्रतिनिधियों की सोवियत करेगी और सामाजिक उत्पादन व उत्पादित मालों के वितरण को राजसत्ता के नियंत्रण में लाना।

राजनैतिक क्षेत्र में लेनिन ने संसदीय लोकतंत्र से सोवियत लोकतंत्र में जाने की बात कही थी। मार्क्सवादी सिद्धांत और उसके प्रयोग के मामले में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले मार्क्सवादी सिद्धांतकार संसदीय लोकतंत्र को ही समाजवाद में जाने का बेहतरीन राजनैतिक ढाँचा मानते थे। लेनिन ने पूँजीवाद से समाजवाद में जाने के दौरान संसदीय लोकतंत्र की बजाय सोवियत लोकतंत्र को ही सबसे उपयुक्त राजनैतिक ढाँचा बताया।

लेनिन ने अपनी थीसिस में रूस की अस्थाई सरकार को समर्थन न देने का आह्वान किया। उन्होंने आगे दिखाया कि सोवियतों में उस समय भी बोल्शेविक अल्पमत में थे। वहाँ मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों का वर्चस्व था, जिन्होंने सर्वहारा वर्ग को बुर्जुआ चिंतन से प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की।

ऐसी स्थिति में लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस में सोवियत समर्थित अस्थाई सरकार के खिलाफ विद्रोह कर उसे उखाड़ फेंकने की बात नहीं कही। वरन् वे चाहते थे कि व्याख्या-विश्लेषण के जरिये सच्चाई जनता को समझायी जाये और इस क्रम में सोवियतों में धीरे-धीरे बोल्शेविकों का बहुमत कायम हो। इस प्रकार उसकी नीतियों में तब्दीली लाकर सोवियतों के जरिये ही सरकार के ढाँचे और नीतियों में परिवर्तन लाया जाये।

लेनिन यह भी चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी अपनी 'गंदी कमीज' को बदल डाले। यानी खुद को 'सोशल डेमोक्रेटिक' पार्टी कहना बन्द करे। दरअसल, दूसरे इंटरनेशनल में शामिल पार्टियाँ और मेंशेविक खुद को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 4 का शेष)

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टियाँ ही कहा करते थे। समाजवाद से विश्वासघात करने वाले और अवसरवादी लोगों ने इस नाम को मटियामेट कर दिया था। लेनिन चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी का नया नाम 'कम्युनिस्ट पार्टी' हो। यही नाम मार्क्स और एंगेल्स ने अपनी पार्टी के लिए चुना था। लेनिन ने कहा कि वैज्ञानिक तौर पर 'कम्युनिस्ट पार्टी' नाम ही सही है; क्योंकि बोल्शेविक पार्टी का अंतिम लक्ष्य है समाजवाद के जरिये 'कम्युनिज्म' तथा साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना, जहाँ 'हर इन्सान अपनी क्षमता के अनुसार समाज के लिए मेहनत करेगा और अपनी जरूरत के अनुसार समाज से लेगा।'

लेनिन की अप्रैल थीसिस के खिलाफ मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। वे मजदूरों को यह कहकर चेतावनी देने लगे थे कि 'क्रांति खतरे में है'। मजदूरों और सैनिकों के प्रतिनिधियों की सोवियत को सारी सत्ता सौंपने की मांग कर रहे थे बोल्शेविक। यही उनके लिए खतरे की वजह थी। प्लेखानोव ने अपनी पत्रिका 'येदींस्त्वो' (एकता) में प्रकाशित एक निबंध में लेनिन की अप्रैल थीसिस की निंदा की। मेंशेविकों की टिप्पणी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ''लेनिन अकेले क्रांति के दायरे से बाहर रह जायेंगे। लेकिन, हम अपने रास्ते आगे बढ़ते रहेंगे।'' मेंशेविकों और अन्य सोशल डेमोक्रेटों का कहना था कि रूस में बुर्जुआ जनवादी क्रांति तो सफल हुई है, लेकिन बुर्जुआ क्रांति के ढेरों काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। इसलिए जब तक इस बुर्जुआ जनवादी क्रांति के आर्थिक और सामाजिक कार्यभार खत्म नहीं हो जाते, तब तक समाजवादी क्रांति का एलान करना हठधर्मिता होगी। उनके मतानुसार नई-नई स्थापित इस पूंजीवादी सरकार का सहयोग करना ही तत्कालीन वामपंथियों का फर्ज था। इसे उखाड़ फेंकने की कोशिश करना उनकी राय में अनैतिहासिक था।

ऐसी परिस्थिति में 14 अप्रैल को पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों के एक सम्मेलन में लेनिन की अप्रैल थीसिस को स्वीकार कर लिया गया और तय हुआ कि उसी के आधार पर आगे के कार्यक्रम संचालित होंगे। इसके कुछ दिनों बाद पार्टी के क्षेत्रीय स्तर के संगठनों ने भी लेनिन की इस थीसिस को स्वीकार कर लिया। नतीजतन, कामेनेव, राइकोव और पियतकोव जैसे चंद लोगों को छोड़कर समूची पार्टी ने जोश-खरोश के साथ लेनिन की थीसिस को स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर काम करना शुरू कर दिया।

अस्थाई सरकार का संकट

बोल्शेविक जब क्रांति की तैयारी में व्यस्त थे, उस दौरान अस्थाई सरकार जनहित के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रही थी। 18 अप्रैल को रूस के विदेश मंत्री ने विश्व युद्ध में रूस के मित्र देशों को जानकारी दी कि जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती, तब तक रूस युद्ध में शामिल रहेगा और मित्र देशों के साथ जार द्वारा किये गये समझौते को मानकर चलेगा। 19 अप्रैल को जब यह घोषणा हुई, तो आम जनता समझ गयी कि जार द्वारा किये गये समझौते को मानने के बहाने इस युद्ध में अस्थाई सरकार साम्राज्यवादियों के हित में आम जनता का खून बेरोक-टोक बहाती रहेगी। 20 अप्रैल को बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने जनता से अस्थाई सरकार की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ विरोध जताने का एलान किया। 20-21 अप्रैल को एक लाख से भी ज्यादा मजदूर और सैनिक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनके झंडे पर लिखा था–'गोपनीय समझौता उजागर करो', 'युद्ध खत्म करो' 'सारी सत्ता सोवियतों को सौंपो' आदि। मजदूर और सैनिक जुलूस की शक्ल में अस्थायी सरकार के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन करते रहे। नेवेस्की प्रोसपेक्टस और दूसरी जगहों पर विभिन्न बुर्जुआ समूहों के साथ उनकी झड़प होती रही। प्रतिक्रांतिकारी जनरल कॉर्निलोव ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। लेकिन सेना ने उसका आदेश मानने से इनकार कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान पेट्रोग्राद पार्टी कमेटी के एक छोटे से समूह ने अस्थायी सरकार को सत्ता से तुरंत बेदखल करने का आह्वान कर दिया। बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने इसे वामपंथी दुस्साहसवाद की संज्ञा देकर इसकी कटु आलोचना करते हुए कहा था कि ऐसा आह्वान करना ठीक नहीं है और ऐसा आह्वान करने का मौका भी अभी नहीं आया है। पार्टी ने जिस तरह सोवियतों में बहुमत हासिल कर क्रांतिकारी संघर्ष को आगे बढ़ाने की योजना बनायी है, यह आह्वान इसे बर्बाद कर देगा।

20-21 अप्रैल की घटना ने अस्थाई सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया। जन आंदोलन के दबाव में सरकार के दो मंत्री इस्तीफा देने को मजबूर हुए। पहली अस्थाई 'गठबंधन' सरकार बनी। इस सरकार में बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों के अलावा मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस प्रकार वे जनता का पक्ष छोड़कर प्रतिक्रांतिकारी बुर्जुआ वर्ग के खेमे में चले गये।

बोल्शेविक पार्टी का अप्रैल सम्मेलन

मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों के विरोध स्वरूप 24 अप्रैल को पार्टी के सातवें सम्मेलन में बोल्शेविकों ने समाजवादी क्रांति के परिपूरक के तौर पर युद्ध, अस्थाई सरकार, सोवियत, कृषि समस्या, राष्ट्रीयता समस्या आदि विषयों पर पार्टी की नीति तय की। पहली बार बोल्शेविक पार्टी खुला सम्मेलन कर सकी। इसी सम्मेलन में नीति के बारे में विभिन्न चर्चाओं में कामेनेव, जेनोवियेव, बुखारिन, राइकोव, पियतकोव आदि नेताओं की अवसरवादी सोच जाहिर हो गयी।

इस सम्मेलन में कामेनेव और राइकोव ने लेनिन का विरोध किया। मेंशेविकों के स्वर में स्वर मिलाकर वे जोर देकर कहते रहे कि रूस अभी भी समाजवादी क्रांति संगठित करने की स्थिति में नहीं पहुँचा है। ऐसे में यहाँ केवल बुर्जुआ लोकतंत्र की स्थापना करना ही मुमकिन है। उनकी राय थी कि ऐसी स्थिति में केवल अस्थाई सरकार को नियंत्रित करने के काम तक ही पार्टी और मजदूर वर्ग खुद को सीमित रखे। वास्तव में मेंशेविकों की तरह वे भी पूँजीवादी व्यवस्था की हिफाजत करने और राजसत्ता को बुर्जुआ वर्ग के कब्जे में रखने के हित में काम कर रहे थे।

जनता को संगठित करने में बोल्शेविक पार्टी की सफलता

अप्रैल सम्मेलन के फैसले के मुताबिक बोल्शेविक पार्टी ने जनता के समर्थन के आधार पर उसे संगठित और प्रशिक्षित करने का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया था। उस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का काम था धैर्य के साथ बोल्शेविक पार्टी की योजना को जनता को समझाना और मेंशेविकों तथा सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों के समझौतापरस्त चरित्र को जनता के सामने उजागर करना और इन सभी पार्टियों के प्रभाव से जनता को मुक्त करना और सोवियतों में बहुमत हासिल करना।

इस दौरान सोवियतों में काम करने के अलावा बोल्शेविक ट्रेड यूनियनों और कारखानों की कमेटियों में भी बड़े व्यापक पैमाने पर काम करते रहे। सेना में भी बोल्शेविकों का काम फैल गया। हर जगह सैन्य संगठन बनने लगा। युद्ध के मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों को सक्रिय क्रांतिकारियों में तब्दील करने के काम में बोल्शेविकों के मुखपत्र 'उकोपनाया प्राव्दा' ने विशेष भूमिका निभायी थी। बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत की बदौलत विभिन्न शहरों में, खासकर जिलों में मजदूरों ने सोवियतों में फिर से चुनाव करवाया और मेंशेविकों व सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों की जगह पर बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों को निर्वाचित किया।

3 जुलाई को पेट्रोग्राद के वाईबर्ग जिले में स्वत:स्फूर्त तौर पर जुलूस-प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शन दिन भर चलता रहा। प्रदर्शनकारियों के छोटे-छोटे जुलूसों ने विशाल शक्ल अख्तियार कर ली। इस सशस्त्र जुलूस में सारी सत्ता सोवियतों को सौंपने की मांग गूँज रही थी। बोल्शेविक पार्टी ने इस दौरान इस सशस्त्र आन्दोलन को समर्थन नहीं दिया। क्योंकि, वे जानते थे कि आम जनता को पूरी तरह से तैयार किये बिना सशस्त्र विद्रोह छिड़ जाने पर प्रतिक्रांतिकारियों के लिए उसे आसानी से कुचल देना संभव होगा। लेकिन जब देखा गया कि किसी भी तरह से जनता के इतने बड़े प्रदर्शन को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं हो रहा है, तो इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से बोल्शेविक पार्टी ने इसमें शामिल होने का फैसला लिया। लाखों की तादाद में स्त्री-पुरुष पेट्रोग्राद में जुलूस-प्रदर्शन कर सारी सत्ता सोवियतों को सौंपने, साम्राज्यवादी बुर्जुआ वर्ग के साथ समझौता रद्द करने और शांति प्रक्रिया को लागू करने की माँग पर गर्मजोशी के साथ नारे लगाते रहे और इसी के साथ आंदोलन आगे बढ़ता गया। लेकिन शांतिपूर्ण होने के बावजूद इस जुलूस पर प्रतिक्रांतिकारी ताकतों ने सशस्त्र हमला किया। पेट्रोग्राद की सड़कें जुलूस में शामिल मजदूरों और सैनिकों के खून से तर-बतर हो गयीं।

प्रदर्शन पर खतरनाक रूप से हमला करने के बाद मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों ने बुर्जुआ वर्ग और सैन्य अधिकारियों की मदद से बोल्शविक पार्टी पर हमला शुरू किया। प्राव्दा, सोलदातस्काया प्राव्दा(सैनिकों का सत्य) सहित बोल्शेविक पार्टी के ढेरों अखबारों को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। वोइनोव नामक एक मजदूर की 'प्राव्दा' बुलेटिन बेचने के जुर्म में सड़क पर खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गयी। चारों ओर गिरफ्तारियाँ होने लगीं। 7 जुलाई को लेनिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। बोल्शेविक पार्टी के कई अगली कतार के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी के अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ जहाँ से छपती थीं, उस छापाखाने को ध्वस्त कर दिया गया।

केरन्स्की, स्कोवेलेव, चर्नोव आदि मेंशेविक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टियों के नेताओं को लेकर गठित अस्थाई गठबंधन सरकार इस तरह प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रांतिकारी करतूतों को अंजाम दे रही थी। शांति बनाये रखने की नीति अपनाने की बजाय इस सरकार ने युद्ध जारी रखने की नीति अपनायी, मजदूरों और सैनिकों को सुरक्षा देने की बजाय हथियारों के बल पर उनके जनवादी अधिकारों को छीनने की निर्मम कोशिश की। रूस के बुर्जुआ वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी जिस काम को करने की जुर्रत नहीं की, उसे 'सोशलिस्ट' नामधारी केरेन्स्की, चेर्नोव आदि नेताओं ने बेहिचक कर डाला।

रूस में दोहरी सत्ता के दिन खत्म हुए। सारी सत्ता को अस्थाई गठबंधन सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। सोवियतें उस सरकार की मात्र पुछल्ला बनी रही। इसके साथ ही क्रांति का शांतिपूर्ण चरण खत्म हुआ। इस बदली हुई परिस्थिति में बोल्शेविक पार्टी ने अपना रणकौशल बदलने का फैसला लिया। लेनिन सहित पार्टी के दूसरे नेताओं के लिए गुप्त ठिकानों का प्रबंध किया गया। साथ ही पूरी पार्टी 'अण्डर ग्राउण्ड' हो गयी। राजलिव स्टेशन के नजदीक एक बस्ती में लेनिन गुप्त रूप से रहने लगे। सशस्त्र बगावत के जरिये बुर्जुआ वर्ग को सत्ता से उखाड़ फेंककर सोवियतों को सत्तासीन करने का लक्ष्य लेकर बोल्शेविक पार्टी ने सरकारी निगरानी से बचकर काफी गोपनीय तरीके से अपनी गतिविधियाँ जारी रखी।

बोल्शेविक पार्टी की छठी कांग्रेस

ऐसी ही स्थिति में काफी गुप्त रूप से कॉमरेड स्तालिन के नेतृत्व में 26 जुलाई से 3 अगस्त तक पार्टी की छठी कांग्रेस आयोजित हुई। अस्थाई सरकार का खुफिया विभाग बड़ी मुस्तैदी के साथ लेनिन को ढूँढ़ रहा था। नतीजतन, लेनिन इस कांग्रेस में उपस्थित नहीं रह सके। लेकिन गुप्त ठिकाने से ही वे स्तालिन, मोलोतोव, अर्दजोनिकिद्जे आदि नेतृत्वकारी साथियों के जरिये मजदूरों को निर्देश भेजते रहे।

छठी कांग्रेस में कुल 157 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस दौरान पार्टी की सदस्य संख्या 2 लाख 40 हजार थी। अंडर ग्राउण्ड हो जाने से पहले बोल्शेविक रूसी और दूसरी भाषाओं में 41 अखबार और पत्र-पत्रिकाएँ निकालते थे।

रूसी क्रांति के इतिहास में बोल्शेविक पार्टी की छठी कांग्रेस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि, इसी कांग्रेस में समाजवादी क्रांति संबंधी लेनिन की ऐतिहासिक थीसिस को काफी तर्क-बहस के बाद आखिरकार मान लिया गया। ट्रॉटस्की और उनके अनुयायी प्रेवब्रोझेस्की, बुखारिन आदि ने समाजवादी क्रांति की थीसिस और उसे सम्पन्न करने के लिए जो रणनीति और रणकौशल लेनिन ने पेश किया था, उसके विपरीत राय व्यक्त की। उनका मानना था कि पश्चिमी देशों में यानी यूरोप के विकसित देशों में जब तक क्रांति संगठित नहीं हो जाती, तब तक रूस के सर्वहारा वर्ग के लिए राजसत्ता पर कब्जा करना मुमकिन नहीं होगा और यदि हुआ भी, तो उसे बरकरार रखना संभव नहीं होगा। उन्होंने चिरस्थायी क्रांति का एक सिद्धांत पेश किया। उनका एक और सिद्धांत यह था कि क्रांति के दौरान सर्वहारा वर्ग को किसानों का साथ नहीं मिलेगा। वे क्रांति के विरोधी बन जायेंगे।

कॉमरेड लेनिन की सीख के आधार पर स्तालिन ने इन सब गलत और अवसरवादी सिद्धांतों को परास्त किया। बुर्जुआ वर्ग की तमाम दमनात्मक कार्रवाइयों के बावजूद किस तरह क्रांति आगे बढ़ रही है, इसे उन्होंने साफ तौर पर दिखाया। स्तालिन ने दिखाया कि रूस की क्रांति धीरे-धीरे

(शेष पृष्ठ 7 पर)

'वाल स्ट्रीट आन्दोलन' के समर्थन में देश भर में एकजुटता जुलूस

महान नवम्बर क्रान्ति.....

(पृष्ठ 5 का शेष)

समाजवादी क्रांति का चरित्र अपनाती जा रही है। यह समाजवादी क्रांति वर्तमान समय में जो फर्ज पूरा करने को कहती है, वह है उत्पादन और वितरण पर मजदूर वर्ग का नियंत्रण कायम करना, किसानों को खेती लायक जमीन मुहैया कराना और बुर्जुआ वर्ग के हाथ से राजसत्ता को छीनकर मजदूरों और गरीब किसानों को सौंपना।

छठी कांग्रेस में बोल्शेविक पार्टी ने हथियारबंद बगावत का रास्ता अपनाने का फैसला लिया। इसलिए सर्वहारा वर्ग और गरीब किसानों को संगठित करने का निर्णय लिया गया। छठी कांग्रेस से जो घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ, उसमें बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ आखिरी लड़ाई के लिए मजदूरों, सैनिकों और किसानों को अपनी सारी ताकत जुटाकर संगठित होने का आह्वान किया गया।

जनरल कार्निलोव की साजिश

इस बीच रूस के बुर्जुआ वर्ग कमजोर सोवियतों को खत्म कर देने तथा खुले तौर पर प्रतिक्रांतिकारी कार्रवाई करने की तैयारी करता रहा। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी केरेन्स्की ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने जमींदारों से जमीन छीनने की कोई भी कोशिश की, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। सेना प्रमुख जनरल कार्निलोव तो कमेटियों और सोवियतों को तुरंत भंग कर देना चाहते थे। बैंकों के मालिक, व्यापारी और कारखानों के मालिक अकूत रुपये-पैसे से जनरल कार्निलोव की मदद करने को तैयार खड़े थे। सहयोगी ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने भी जनरल कार्निलोव को समर्थन जताकर क्रांति के खिलाफ तुरंत कदम उठाने की जरूरत बतायी।

25 अगस्त को 'पितृभूमि की रक्षा' के नाम पर कार्निलोव ने जनरल क्राइमोव की कमान में पेट्रोग्राद में सेना भेजने का प्रबंध किया। इस हमले का सामना करने के लिए बोल्शेविक पार्टी ने मजदूरों और सैनिकों को सक्रिय रूप से सशस्त्र प्रतिरोध करने का आह्वान किया। मजदूरों ने शीघ्र ही प्रतिरोध के लिए हथियार लेकर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। चारों तरफ लाल फौज की अनगिनत छावनियाँ बन गयीं। ट्रेड यूनियनों ने अपने मजदूर सदस्यों को प्रतिरोध संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया। पेट्रोग्राद की क्रांतिकारी फौज युद्ध के लिए तैयार होने लगी। पेट्रोग्राद के चारों ओर खाई खोद दी गयी, कंटीले तारों की बाड़ लगा दी गयी, शहर की ओर से आ रही ट्रेन की पटरियाँ ध्वस्त कर दी गयीं। जहाँ से भी कार्निलोव के सैनिकों के हमले की संभावना थी, वहाँ बोल्शेविक पार्टी ने क्रांतिकारी कमेटियाँ और क्रांतिकारी हैड क्वार्टर्स, हाई कमान कायम कर दी थी।

इस दौरान मौत के भय से भयभीत अपनी सुरक्षा के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों और मेंशेविकों ने, जिनमें केरेन्स्की भी था, बोल्शेविकों के पास आकर शरण मांगी। वे समझ गये थे कि पेट्रोग्राद में जनरल कार्निलोव को परास्त करने की क्षमता एकमात्र बोल्शेविकों में ही है। इसी बीच, कार्निलोव के हमले का जवाब देने के लिए बोल्शेविक जनता को संगठित करने के साथ-साथ जनता में केरेन्स्की सरकार, मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों को बेनकाब करने का काम भी समान महत्व देकर करते रहे। उन्होंने व्याख्या-विश्लेषण कर दिखाया था कि इनकी तमाम गतिविधियाँ और नीतियाँ वास्तव में कार्निलोव की प्रतिक्रांतिकारी साजिश को ही आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं। इन सब के नतीजतन अंततः कार्निलोव के हमले को रोक दिया गया था। कार्निलोव की इस पराजय ने रूसी जनता के समक्ष कुछ मुद्दों को साफ उजागर कर दिया था। पहली बात तो यह साफ हो गयी थी कि प्रतिक्रांतिकारियों की तुलना में क्रांतिकारी अधिक ताकतवर हैं। कार्निलोव की पराजय ने यह भी दिखा दिया था कि क्रांति की निर्णायक शक्ति के रूप में बोल्शेविक पार्टी संगठित हो चुकी है और यह पार्टी प्रतिक्रांति की किसी भी साजिश को नाकाम करने की क्षमता रखती है। अंत में इस पराजय से यह साबित हो गया था कि जिन सोवियतों को कमजोर समझा गया था, वास्तव में उनमें प्रतिक्रांति को रोकने की सारी क्षमता सुप्तावस्था में मौजूद थी। सोवियतों और उसकी क्रांतिकारी कमेटियों ने कार्निलोव की सेना को रोककर उसकी सारी ताकतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बात में अब कोई सन्देह नहीं रहा था।

कार्निलोव के खिलाफ प्रतिरोध संघर्ष ने मुरझायी हुई सोवियतों में फिर से नई जान फूँक दी थी। इस संघर्ष ने समझौतापरस्त ढुलमुल मानसिकता को खत्म कर उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष के खुले मैदान में ला खड़ा किया था और बोल्शेविक पार्टी के प्रति आकर्षण भी काफी बढ़ा दिया था। सोवियतों में बोल्शेविकों का प्रभाव काफी बढ़ गया था। सिर्फ शहरों में ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न जिलों में भी बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ गया था। छोटे और मझौले किसान बड़ी तादाद में बोल्शेविक पार्टी के प्रति आकर्षित हुए थे। 1917 के सितम्बर और अक्टूबर महीने में किसानों ने मालिकों से बड़े पैमाने पर जमीन छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। क्रांति के स्वप्न से अनुप्राणित इन किसानों को सजा देकर या और किसी भी तरह रोका नहीं जा सका था। रूस में उस दौरान क्रांति की लहर अपने उफान पर थी।

उस दौरान सोवियतों में नये सिरे से मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों की जगह पर बोल्शेविक पार्टी के प्रतिनिधियों को चुनने का दौर शुरू हुआ और फिर से यह मांग उठी कि 'सोवियतों को सारी सत्ता सौंपो'। इस बार के नारे का लक्ष्य था अस्थायी सरकार को राजसत्ता से पूरी तरह से हटाकर बोल्शेविकों द्वारा संचालित सोवियत को सारी सत्ता का हस्तांतरण करना।

समझौतापरस्त पार्टियों में भी टूटन पैदा हुई। मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों में से काफी लोग बोल्शेविकों की तरफ आ गये थे।

कार्निलोव की पराजय के बाद मेंशेविकों और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों ने फिर एक बार क्रांति की लहर को रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने 12 सितम्बर, 1917 को समझौतापरस्त सोवियतों, ट्रेड यूनियनों आदि को लेकर एक ऑल रूस डेमोक्रेटिक कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया। इस कॉन्फ्रेंस ने एक प्राक-संसद (पार्लियामेंट की स्थापना के लिए एक प्राथमिक परिषद्) गठित की। बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने इस प्राक-संसद का बहिष्कार करने का फैसला लिया। लेकिन कामेनेव, जिनोवियेव आदि ने मेंशेविकों के स्वर में स्वर मिला कर कहना शुरू कर दिया कि खतरे में पड़ी बुर्जुआ सरकार की अभी मदद करनी चाहिए और इस प्राक-संसद में भी शामिल होना चाहिए। लेकिन लेनिन ने दिखाया कि ऐसा करने का अर्थ होगा आम जनता में बुर्जुआ संसद के प्रति मोह पैदा करना और क्रांति की चाहत को गलत रास्ते पर ले जाना।

बोल्शेविक हथियारबंद बगावत की तैयारी में लगे रहे। बगावत के दौरान सेना की यूनिटें, लाल फौज और नौसेना के क्रांतिकारी पेट्रोग्राद शहर के किस-किस स्थान से लड़ाई का संचालन करेंगे, इन सारे विषयों को समेटकर लेनिन ने एक सर्वव्यापक योजना तैयार की।

7 अक्टूबर को लेनिन काफी गुप्त रूप से पेट्रोग्राद में उपस्थित हुए। 10 अक्टूबर को बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की एक ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई, आने वाले कई दिनों के अन्दर किस तरीके से हथियारबंद बगावत की जायेगी, इसी आशय का निर्णय इस बैठक में लिया गया। केन्द्रीय कमेटी के दो सदस्यों कामेनेव और जिनोवियेव ने इस ऐतिहासिक फैसले का विरोध किया। मेंशेविकों की तरह वे भी बुर्जुआ संसदीय लोकतंत्र का ख्वाब देख रहे थे। इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं था कि मजदूर वर्ग समाजवादी क्रांति सफल करने की क्षमता हासिल कर चुका है। इसी बैठक में ट्रॉटस्की ने भी बगावत की तारीख को आगे बढ़ाकर सोवियतों की दूसरी कांग्रेस के बाद उसकी शुरूआत करने को कहा था।

बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी ने दक्षिण-पश्चिम मोर्चे सहित देश के विभिन्न स्थानों पर बगावत संगठित करने के लिए वोरोशिलोव, मोलोतोव, जेरझिनस्की, अर्दजोनिकिद्जे, किरोव, कागानोविच आदि नेताओं को विभिन्न प्रदेशों में भेज दिया था। पेट्रोग्राद में बगावत की शुरूआत होते ही देश भर में संघर्ष फैल जाये, इसी वजह से इन लोगों को भेजा गया था। पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के निर्देश पर पेट्रोग्राद सोवियत की एक क्रांतिकारी सैन्य कमेटी का गठन किया गया था। पूरी बगावत के हेडक्वार्टर के रूप में इस कमेटी ने काम किया था।

16 अक्टूबर को केन्द्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की एक 'कोर कमेटी' चुनी गयी थी और कॉमरेड स्तालिन को आसन्न बगावत में नेतृत्व प्रदान करने के लिए मनोनीत किया गया था। यह कोर कमेटी ही पेट्रोग्राद सोवियत की क्रांतिकारी सैन्य कमेटी का नेतृत्वकारी हिस्सा थी और पूरी बगावत इस कोर कमेटी के दिशा-निर्देशन में ही हुई थी। 16 अक्टूबर की बैठक में भी जिनोवियेव और कामेनेव ने फिर बगावत का विरोध किया और अखबारों में बयान देकर बोल्शेविकों की बगावत की योजना को सार्वजनिक कर दिया।

इधर विश्वासघातियों से खबर पाकर प्रतिक्रांतिकारी हमले की योजना बनाने लगे थे। 19 अक्टूबर को अस्थाई सरकार ने मोर्चे से सेना को वापस बुलाकर पेट्रोग्राद में तैनात कर दिया था। सड़कों पर सेना की गश्त जारी थी। सरकार की योजना बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी के हेडक्वार्टर स्मोलनी भवन पर हमला बोलकर उस पर कब्जा कर लेने की थी।

इसी बीच, पेट्रोग्राद सोवियत की एक बैठक में हथियारबंद बगावत की गोपनीय तारीख को ट्रॉटस्की ने सार्वजनिक कर दिया। नतीजतन, बोल्शेविक पार्टी की केन्द्रीय कमेटी को उस तयशुदा तारीख से पहले ही बगावत शुरू करने की योजना तैयार करनी पड़ी। उन्होंने तय किया कि सोवियत की दूसरी कांग्रेस आरंभ होने के पहले दिन ही हथियारबंद बगावत की शुरूआत की जाये।

दुनिया को हिला देने वाला दिन

24 अक्टूबर (नये कैलेंडर के अनुसार 6 नवम्बर) की सुबह ही बोल्शेविक पार्टी के केन्द्रीय मुखपत्र 'राबोचिपूत' (मजदूरों की राह) को बन्द करके और अखबार के सम्पादकीय कार्यालय तथा छापेखाने पर बख्तरबंद गाड़ियां तैनात करके केरेन्स्की सरकार ने हमले की शुरूआत कर दी। हालांकि, स्तालिन के निर्देशानुसार लाल फौज और क्रांतिकारी सैनिकों ने बख्तरबंद गाड़ियों को वहाँ से खदेड़ दिया। उसी दिन 11 बजे के करीब अस्थाई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ राबोचिपूत अखबार प्रकाशित हुआ। साथ ही पार्टी कोर के निर्देश पर क्रांतिकारी सैनिकों की विभिन्न टुकड़ियाँ और लाल फौज स्मोलनी भवन के पास जल्दी ही तैनात कर दी गयी। अब बगावत शुरू हो गयी। उसी रात को लेनिन स्मोलनी भवन पहुँच गये थे और खुद मौजूद रहकर बगावत का नेतृत्व किया था। रात भर क्रांतिकारी सैनिक स्मोलनी भवन आते रहे। बोल्शेविकों ने उन्हें शीत प्रासाद को घेरने के लिए भेज दिया था। उसी शीत प्रासाद में अस्थाई सरकार के अधिकारी आश्रय लिये हुए थे।

25 अक्टूबर (नये कैलेण्डर के अनुसार 7 नवम्बर) को क्रांतिकारी फौज ने रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलिग्राफ ऑफिस, मंत्रियों के कार्यालय और स्टेट बैंक को कब्जे में ले लिया था। प्राक-संसद को भंग कर दिया गया था। स्मोलनी भवन क्रांति का हेडक्वार्टर बन गया था। इस दौरान लाल फौज के साथ पेट्रोग्राद के मजदूरों ने बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में असाधारण वीरता का परिचय दिया था। नौसेना भी पीछे नहीं रही थी। युद्धपोत 'अरोरा' ने शीत प्रासाद को अपनी तोप का निशाना बनाया था।

उसी दिन यानी 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने रूसी जनता के बीच एक घोषणा-पत्र वितरित करके बताया था कि बुर्जुआ अस्थाई सरकार को सत्ता से बेदखल कर सोवियतों ने राजसत्ता पर कब्जा कर लिया है। उस दिन रात को क्रांतिकारी मजदूरों, सैनिकों और नौसैनिकों ने शीत प्रासाद पर कूंच कर अस्थाई सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। पेट्रोग्राद की हथियारबंद बगावत में बोल्शेविक विजयी हुए थे। राजधानी की शासन व्यवस्था पेत्रोग्राद सोवियत के हाथ में चली गयी थी। रूस में एक नयी किस्म की राजसत्ता-समाजवादी सोवियत राजसत्ता का गठन हुआ। जमीन पर से जमींदारों का नियंत्रण खत्म कर उसे किसानों में बाँट दिया गया। सारी जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। पूँजीपतियों की सम्पत्ति राजसत्ता द्वारा जब्त कर ली गयी थी। युद्ध से अपने को अलग कर सोवियत रूस ने समाजवादी समाज के निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी।

नवम्बर की समाजवादी क्रांति ने पूँजीवाद को ध्वस्त कर पूँजीपतियों से उत्पादन के साधनों को छीन लिया था और तमाम कल-कारखानों, जमीनों, रेलवे और बैंकों को जनता की सम्पत्ति में तब्दील कर उसे देश की मेहनतकश जनता के हवाले कर दिया गया था।

नवम्बर क्रांति ने रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व कायम किया और इस विशाल देश की शासन व्यवस्था मजदूरों के हवाले कर उन्हें शासक वर्ग में तब्दील कर दिया था।

इस तरह नवम्बर क्रांति ने मानव सभ्यता के इतिहास में एक नये युग-सर्वहारा क्रांति के युग-की शुरूआत की थी।

(समाप्त)

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-12/1123/2009-2011
Posting at IPMBC on 7-8 and 22-23 of Every Month

साम्राज्यवादियों के उकसावे पर की गई कर्नल गद्दाफी की नृशंस हत्या की

आईएपीएससीसी द्वारा घोर निन्दा

संयुक्त राज्य अमेरिका-नीत साम्राज्यवादी ताकतों की प्रत्यक्ष मदद से तथाकथित विद्रोहियों द्वारा किये गये कर्नल गद्दाफी के नृशंस हत्याकाण्ड की घोर निन्दा करते हुए इन्टरनेशनल एंटी-इम्पीरियलिस्ट एण्ड पिपल्स सोलिडेरिटी कॉआर्डिनेटिंग कमेटी (आईएपीएससीसी) ने 21 अक्तूबर को एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि लोकतंत्र और नागरिकों की रक्षा करने के नाम पर अमेरिकी-नाटो फौजों ने लिबिया की सम्प्रभुता पर वहशियाना हमला किया है। यह घटना विभिन्न देशों में शासकों के परिवर्तन की साम्राज्यवादियों की नीति की ही एक मिसाल है। ठीक इसी तरह साम्राज्यवादी ताकतों ने इराक और अफगानिस्तान में बेहद खुंखार ढंग से शासक बदले हैं। लिबिया या किसी भी दूसरे देश के अन्दरूनी मामले में दखलअंदाजी करना या उस देश के लोगों पर कोई मनमानी राजनीतिक व्यवस्था थोप देने का साम्राज्यवादियों को कोई अधिकार नहीं है। अपने-अपने शासक और शासन व्यवस्था को चुनने का अधिकार एक देश के नागरिकों को ही है। दरअसल, लिबिया में अपने नियंत्रण के अधीन एक कठपुतली सरकार बिठा कर वहां अपना राजनैतिक व आर्थिक वर्चस्व कायम रखना ही साम्राज्यवादियों का मन्सूबा है।

लिबिया के बाद सीरिया, यमन, बहरीन आदि मध्यपूर्व के बाकी देशों पर भी इसी तरह हमले बोलने का मन्सूबा साम्राज्यवादियों का है यह कहते हुए आईएपीएससीसी ने गहरी चिन्ता प्रकट की है। दुनिया के तमाम प्रगतिशील और आजादी पसन्द अवाम को विरोध में आगे आकर साम्राज्यवादी ताकतों की हमलावर घिनौनी मंशा के खिलाफ देश-देश में जनआन्दोलन गठित करने का आह्वान करते हुए कमेटी ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि पूंजीवादी शोषण-उत्पीड़न से त्रस्त लोगों का आक्रोश रोजी-रोटी व मकान और शोषणमुक्ति के लक्ष्य से उत्पीड़क शासकों के खिलाफ स्वत:स्फूर्त विक्षोभ आन्दोलनों में फूट पड़ रहा है। लेकिन इन आन्दोलनों के जरिए अगर सही क्रांतिकारी नेतृत्व नहीं उभर कर आया, तो अवाम की चाह पूरी नहीं होगी और साम्राज्यवादी बार-बार इन आन्दोलनों को गुमराह कर देने की साजिश रचेंगे, इनका इस्तेमाल अपने तुच्छ स्वार्थों को साधने में करेंगे और साम्राज्यवादियों की शह से करवाये जाने वाले कार्यकलापों पर 'लोकतंत्र की मांग पर आन्दोलन' का ठप्पा लगा देंगे। इसलिए आज जरूरत है पूंजीवाद-विरोधी समाजवादी क्रांति के अन्तिम लक्ष्य को सामने रखकर विभिन्न देशों के साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलनों को संगठित व संयोजित करना।

कार्ल मार्क्स सदी के सबसे श्रेष्ठ चिन्तनकार

पूरी दुनियाभर में पूंजीवादी-साम्राज्यवादी व्यवस्था के संकट काल में बीबीसी न्यूज ऑनलाइन में वोट देकर दर्शकों ने 20वीं सदी के श्रेष्ठ चिन्तनकार के तौर पर मजदूर वर्ग के मुक्ति-संघर्ष के पथ प्रदर्शक महान दार्शनिक कार्ल मार्क्स को चुना है। ब्रिटेन से प्रसारित होने वाले समाचार माध्यम बीबीसी न्यूज ने 20वीं सदी का श्रेष्ठ चिन्तनकार मनोनीत करने के लिए हाल ही में दर्शकों को मत देने का आह्वान किया था। इसमें पूरी दुनिया के असंख्य लोगों ने हिस्सा लिया था।

विश्व समाजवादी खेमे के पतन से दुनिया के पूंजीवादी शासक और सिद्धांतकार हर्षोल्लास से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मानव सभ्यता में पूंजीवाद ही अन्तिम बात है। पूंजीवादी संकट के समाधान की मुश्किल को आसन करने के लिए निदान के तौर पर इन्होंने भूमण्डलीकरण और उदारीकरण का टोटका अपनाया था। लेकिन फिर भी वे संकट से उबर नहीं पा रहे हैं। बल्कि पूरी दुनिया की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगातार और भी गहरे संकट से ग्रस्त होत जा रही है। महामंदी के धक्के से एक पर एक देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने जैसे हालात पैदा होते जा रहे हैं। दरअसल सारी दुनिया ही अब पूंजीवादी-साम्राज्यवादी बाजार के खुले मैदान में तब्दील हो गई है। फिर भी पूंजीवाद क्यों उत्पादन और बाजार संकट में डूबता जा रहा है? पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था की चीरफाड़ करके कार्ल मार्क्स ने दिखाया था कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था ही उसके खुद के संकट को न्यौता देती है। पूंजीवाद के संकट की जड़ खुद इस व्यवस्था में ही निहित है। मार्क्सवाद-विरोधी दुनियाव्यापी अंधाधुंध प्रचार के बावजूद इन्हीं कार्ल मार्क्स के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है।

दुनिया के लगभग तमाम देशों में ही बेरोजगारी आज जबरदस्त रूप से बढ़ती जा रही है। महंगाई की मार से जनजीवन बेहाल है। आदमी आदमी के बीच आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी की खाई घटने की बजाए और भी चौड़ी होती जा रही है। समस्याग्रस्त होकर आम लोगों का विक्षोभ फूट पड़ रहा है। मध्यपूर्व, अफ्रीका, युरोप के विभिन्न देशों में मेहनतकश जनता सड़कों पर उतर पड़ी है, आन्दोलनों में शामिल होती जा रही है। यही हकीकत चिन्तनशील लोगों को नये सिरे से सोचने पर मजबूर कर रही है। जो लोग ईमानदारी से दुनियाभर में वर्तमान आर्थिक संकट की जड़ को समझना चाह रहे हैं और समाधान का रास्ता खोजना चाह रहे हैं, सचमुच में मेहनतकश जनसाधारण को शोषण, जुल्म, वंचना, हाहाकार से मुक्त कराने की बात सोच रहे हैं उन्हें मार्क्सवाद की ओर लौट कर आना ही पड़ेगा।

हरियाणा में राजनैतिक शिक्षण शिविर

शिक्षण शिविर का संचालन करते हुए कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती

भिवानी: एसयूसीआई(कम्युनिस्ट), हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से यहां 9 से 11 अक्तूबर तक तीन दिवसीय राजनैतिक शिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसका संचालन पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती ने किया। उन्होंने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के कुछ पहलुओं, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष चिन्तनधारा और लेनिनीय मॉडल की कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन सम्बन्धी नियमों पर विस्तार से चर्चा की। राज्य के विभिन्न जिलों से आये पार्टी सदस्यों, समर्थकों व हमदर्दों ने इसमें भाग लिया।

पश्चिम बंग राज्य साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन

शोषक-शासक वर्ग व उसके चाटुकार बुद्धिजीवी अब साम्राज्यवाद शब्द को ही लगभग जबान पर नहीं लाना चाहते हैं। भूमण्डलीकरण का ढिंढ़ोरा पीट कर कॉरपोरेट मीडिया दिखाना चाहता है कि दुनिया अब मानो वर्गसंघर्षहीन नन्दन कानन है, जहाँ हमेशा लोकतंत्र के फूल बरसते हैं, देश-देश में साम्राज्यवादी हमलों और विभिन्न देशों में हो रहे बेतहाशा शोषण से कंगाल-बदहाल लोगों की बढ़ती संख्या से यह साफ जाहिर होता जा रहा है कि यह अत्यन्त कपोल कल्पित झूठ है। साम्राज्यवादियों-पूँजीपतियों के लिए इस झूठे प्रचार में इस तरह बाजी मार लेना सम्भव नहीं होता अगर सीपीएम-सीपीआई जैसी नकली मार्क्सवादी या नकली कम्युनिस्ट पार्टियों ने साम्राज्यवाद-विरोध की न्यूनतम जिम्मेदारी को भी तिलांजलि न दी होती और सत्ता की दौड़ में पागल न हुई होती। जिस तरह साम्राज्यवादी हमले और घुसपैठ रुकी नहीं, उसी तरह उनके खिलाफ प्रतिवाद-प्रतिरोध आन्दोलन भी नहीं हो पाया, जिसकी मुँह बोलती मिसाल है प्राच्य, उत्तर अफ्रीका यहाँ तक कि यूरोप के विभिन्न देश।

समाजवादी खेमे के पतन के नतीजे के तौर पर साम्राज्यवादी युद्ध खेमा मजबूत होकर विभिन्न देशों की आजादी और सम्प्रभुता पर हमले करेगा, इस सही निष्कर्ष से ही 1995 में ऑल इण्डिया एण्टी इम्पीरियलिस्ट फोरम कायम हुआ था। उसके बाद 2007 में इन्टरनेशनल एण्टी इम्पीरियलिस्ट एण्ड पीपुल्स सॉलिडेरिटी कॉ-ऑर्डिनेशन कमेटी गठित हुई ताकि देश-देश में साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलनों के बीच तालमेल कायम किया जा सके। इसी अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी का तीसरा सम्मेलन आगामी 27-29 नवम्बर को ढाका में आयोजित होगा। उसके मद्देनजर भारत के विभिन्न राज्यों में ऑल इण्डिया एण्टी इम्पीरियलिस्ट फोरम के राज्य सम्मेलन हो रहे हैं। 18 सितम्बर को कलकत्ता के मौलाली युवा केन्द्र में पश्चिम बंग राज्य सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी तैयारी में विभिन्न जिलों में गाँव, तहसील, जिला स्तरीय बैठकें, सभाएं, कन्वेन्शन हुए। देश-देश में साम्राज्यवादी नृशंस हमलों और उनके खिलाफ जन-विक्षोभ की चित्र प्रदर्शनी और विडियो दिखाए गए। इसके उपलक्ष्य में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

प्रो गोरी शंकर घटक की अध्यक्षता में और 300 लोगों की उपस्थिति में हुए राज्य सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव पर विभिन्न जिलों के नेताओं ने चर्चा बहस की। विशिष्ट वक्ताओं में शामिल थे प्रो. तरुण सान्याल, प्रो. सुलेमान खुर्शीद और अमिताभ चट्टोपाध्याय। ऑल इण्डिया एंटी इम्पीरियलिस्ट फोरम के महासचिव प्रो. ध्रुव ज्योति मुखोपाध्याय इसमें उपस्थित थे। शिक्षा-स्वास्थ्य और कृषि ही नहीं, बल्कि खासकर संस्कृति के क्षेत्र में साम्राज्यवादियों द्वारा किये जा रहे भयंकर हमलों को लेकर प्रतिनिधियों ने काफी उद्वेग प्रकट किया। सम्मेलन से प्रो. गोरी शंकर घटक को अध्यक्ष और डॉ. महुआ नन्द को सचिव चुनते हुए नई राज्य कमेटी गठित की गई।

साम्राज्यवाद-विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
27-29 नवम्बर, ढाका, बंगलादेश
24 देशों से प्रतिनिधि शामिल होंगे
आई ए पी एस सी सी

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया की ओर से कॉ. गिरिजेश्वर सिंह द्वारा 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली-5 से संपादित व प्रकाशित तथा परम्परा प्रिंटिंग प्रेस, बी-70/83, इण्डस्ट्रियल एरिया, लॉरेंस रोड, दिल्ली-35 से मुद्रित, दूरभाष: 011-25726631, E-mail: sarvaharadrishtikon@yahoo.com